

TIRUPATI BALAJI CHRONICLE

Vol./Year-8 Issue - 44

Hindi / English (Bi-Lingual) Weekly Ghaziabad
केन्द्र एवं उ०प्र० सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

www.tbcgzb.com

News of the Week

,d ebZ l s i V / k s y & M h t y d h d h e r a g j j k s t c n y x h A l j d k j h r s y d a f u ; k a ' k q v k r e a ; g 0 ; o L F k k i k p ' k g j k a m n ; i g] t e ' k n i g] p d h x < } i M p j h v k s j f o ' k k [k k i R r u e e a y k x w d j j g h g A

Inside Ghaziabad

पेज नंबर 2

v k o k l j k T ; e a h d h c B d e a H k h m B k e V / k s --

पेज नंबर 5

Now, 'like' Ponzi scam in Ghaziabad



thMh, ohl h fot ;
; kno dk rcknyk
xkft ; kckn % गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विजय यादव का बुधवार को शासन ने तबादला कर दिया गया। उन्हें फिलहाल कोई जिम्मेदारी न देते हुए वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। वर्ष 2015 में संतोष यादव के जीडीए उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद 20 मई 2015 को विजय यादव को सपा शासन में जीडीए उपाध्यक्ष तैनात किया गया था। वे नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ पद से ट्रांसफर होकर जीडीए आए थे।
fj'or ds vkjksi h batfufu; j dksHkst k tsy
xkft ; kckn % विशेष सीबीआई कोर्ट तीन के जज ने आगरा कैंट से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर अशोक कुमार पाठक को 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इंजीनियर को मंगलवार को सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वह नोएडा की कंपनी रुद्राक्ष एंटरप्राइजेज के ठेकेदार से 50 हजार रुपये घूस ली थी। जिसके कारण यह कार्रवाई की गई।
fuBkj h d k M d s v k j k s i h d k V / e a g g i s k
xkft ; kckn % निठारी कांड के दोनों आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर व सुरेंद्र कोली विशेष सीबीआई जज पवन कुमार तिवारी की अदालत में पेश हुए। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 17 अप्रैल की तारीख लगाई है। सुरेंद्र कोली को कड़ी सुरक्षा के बीच डासना जेल से पुलिस ने पेश किया, जबकि मोनिंदर पंधेर जमानत पर है।

fuxe eagk f M k y x k u s d k v o k [k s y ' k q

fyad j k M o t h V h j k M i j v u e f r l s T ; k n k y x k f n , x , g s g k f M k] d j j g s d k y h d e k b Z

Xkkt ; kckn % गाजियाबाद नगर निगम में फिर से अनुमति से ज्यादा होर्डिंग लगाकर काली कमाई करने का खेल शुरू हो गया है। जीटी रोड व लिंक रोड के अलावा एनएच-2, करहैडा बाईपास, सीआईएसएफ रोड व गाजियाबाद के कई अन्य स्थानों पर फिर से अवैध होर्डिंगों की भरमार हो गई है। नगर निगम के कुछ अधिकारी इस काली कमाई को जमकर लूट रहे हैं। कई स्थानों पर लगे होर्डिंग टेढ़े तक हो रहे हैं जिनसे हादसे की आशंका बनी रहती है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जगह-जगह अवैध होर्डिंग लगे होने से जनपद गाजियाबाद



स्मार्ट सिटी से भी दूर होता जा रहा है। जीटी रोड की ही बात



करें तो कई स्थानों पर तो अभी तक नेताओं के बधाई संदेश तक

लगे हुए हैं जिन्हें हटाया नहीं गया है। लोगों का आरोप है कि होर्डिंगों से काली कमाई का यह खेल नगर निगम की सह पर चलता है। जिसका हिस्सा सभी में बटता है। जब इन्हें हटाने का दबाव आता है तो कुछ दिन के लिए इन्हें हटा दिया जाता है लेकिन फिर दोबारा से लगवा दिया जाता है। इन अवैध होर्डिंगों के कारण हादसों की भी आशंका बनी रहती है। वर्ष 2016 में इन अवैध होर्डिंगों के कारण कई हादसे गाजियाबाद में हो चुके हैं। जिसमें लोगों की जान तक जा चुकी है लेकिन बावजूद इसके नगर निगम इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

xkft ; kckn f o d k l i k f / k d j . k e a t k p d h v k p ' k q

Xkkt ; kckn % जीडीए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) में अब कैंग (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) की पांच सदस्यीय टीम ने सोमवार को फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया है। जिससे जीडीए में कई घोटाले के खुलने की बात सामने आ रही है। प्राधिकरण का सालाना बजट 2500 करोड़ रुपये है। शासन के आदेश के बाद सोमवार सुबह 10 बजे पांच सदस्य कैंग टीम जीडीए पहुंच गई। टीम को देखकर सभी जीडीए अधिकारी व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। टीम के लिए कोई भी कार्यालय तय न होने के कारण टीम के सभी सदस्यों को वित्त नियंत्रक कक्ष में बैठाया गया। उन्होंने वहीं से अपना काम शुरू कर दिया। टीम ने अधिकारियों से विभिन्न विभागों की फाइलें मंगवाने का कार्य शुरू कर दिया और उनकी जांच करने लगी। गौरतलब है कि प्राधिकरण के विकास कार्यों को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। शासन और अधिकारी लगातार ऑडिट से बचते रहे हैं। पिछले सप्ताह शुक्रवार को भी प्राधिकरण

Okbyka dh fyLV d s x V h e d k s l k s h x b Z
xkft ; kckn % ऑडिट के लिए जीडीए की तरफ से फाइलों की लिस्ट बनाकर बुधवार को कैंग टीम को सौंपी गई। कामकाज और लेन-देन की जांच को पहुंची कैंग टीम को जो फाइलें संदिग्ध लगेंगी, उन्हें मंगाकर बारीकी से चेक किया जाएगा। बुधवार दोपहर बाद जीडीए सभागार में कैंग टीम और प्राधिकरण अफसरों की बैठक हुई। बैठक के दौरान कैंग टीम की अध्यक्षता ऑडिटर जनरल विनीता मिश्रा ने की।

के अधिकारियों ने कैंग टीम को लौटा दिया था। उसके बाद आनन-फानन में सात अप्रैल की देर रात प्रमुख सचिव आवास सदाकांत ने कैंग से जीडीए का ऑडिट करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद कैंग के अधिकारियों की इसकी सूचना भेज दी गई थी। 'k s k i s t p k j i j

Speed up repair work in bus depot: Minister

Ghaziabad: A day after he inspected the bus depot in Sector 35 of Noida, Swatantra Dev Singh, minister of state (independent charge), transport, paid a surprise visit to the Kaushambi Bus Stand and Sahibabad Bus Depot in Ghaziabad on Monday. At the Kaushambi depot, Singh asked the UP State Road Transport Corporation (UPSTRC) officials to finish the repair work at the depot within 100 days. About 600 buses run from the Kaushambi depot everyday. He also checked the buses for cleanliness, amenities, customer satisfaction, behaviour of drivers and conductors and the operational frequency of the buses across the district. Meanwhile, at the Sahibabad depot, Singh asked the technical staff not to smoke or consume alcohol in front of their children. The minister also



asked the bus passengers if they were getting water bottles in AC buses. The bus operators in Ghaziabad can face penalty for not providing half-litre water bottle in AC buses. "Five different kinds of buses including AC buses, mini buses, roadways buses were inspected for cleanliness. CCTV cameras and panic buttons have been proposed for the AC buses," said P K Bose, regional manager, UPSRTC. "In the coming 100 days, we will try to provide 100% connectivity to motorable routes in villages under Ghaziabad and Hapur districts and 90% connectivity in villages in Bulandshahr district," Bose said.

पांडव नगर में 11 साल की एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव मकान में कमरे की खिड़की से रस्सी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, रिपोर्ट में मौत का कारण लटकने के कारण मौत का आया है। इस संबंध में परिजनों द्वारा पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस भी मामले को आत्महत्या से जोड़कर चल रही है। मामला कविनगर थाना क्षेत्र का है। कविनगर थाना प्रभारी हेमंत राय ने बताया कि मूलरूप से अलीगढ़ का रहने वाला छोटेलाल पिछले काफी समय से पांडव नगर औद्योगिक

क्षेत्र में रहता है और एक सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी करता है। पत्नी की पूर्व में मौत हो चुकी है, इसके बाद से वह एक पुत्र व पुत्री गुंजन (11) के साथ रहता था। गुंजन पढ़ाई नहीं करती थी घर पर ही रहती थी। सोमवार देर शाम गुंजन खिड़की पर रस्सी के फंदे से लटकी मिली। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण लटकने से मौत आया है।

तलाक के मुकदमे की पैरवी के लिए पेशी पर आए जीजा—साले में जमकर मारपीट हुई। मौके पर पहुंचे अधिवक्ताओं ने बीच—बचाव किया। दोनों ने कविनगर थाने में तहरीर दी है।

प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ताओं के मुताबिक कोर्ट में पेशी के बाद साला अपने अधिवक्ता के चौंबर से बाहर निकल रहा था, इसी दौरान जीजा भी उसी रास्ते पर सामने से आ गया और किसी बात को लेकर कमेंट कर दिया। पहले दोनों में गाली—गलौज हुई, बाद में मारपीट हो गई। साले ने पत्थर उठाकर जीजा को मारने का प्रयास किया। जीजा ने पत्थर छीनकर लात—घूंसों से जमकर धुनाई कर दी।

प्रशासन ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की घेराबंदी तेज कर दी है। सीडीओ के आदेश के बाद सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं ने केंद्रों का निरीक्षण कर करीब 80 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अनुपस्थित दर्शाया है। सूत्रों के मुताबिक, गैरहाजिर कार्यकत्रियों का मानदेय काटने की तैयारी विभाग ने शुरू कर दी है। उधर, भूखहड़ताल के कारण बिगड़ी आंगनबाड़ी कार्यकत्री की हालत में सुधार की बात डाक्टरों ने कही है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। अभद्रता के आरोप में बर्खास्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री की बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर कलक्ट्रेट में चल रहा धरना रुख बदलता दिख रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने जहां बुधवार को कलक्ट्रेट में धरना जारी रखा, वहीं एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली

पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी। जिस कारण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, दोपहर के बाद सभी ऑटो चालकों ने हड़ताल को समाप्त कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बुधवार सुबह सात बजे ओलंपिक तिराहे पर ऑटो चालक एकत्र हुए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ऑटो चालकों ने ओलंपिक तिराहे से बस अड्डे तक पैदल मार्च निकाला। इसके बाद सभी आटो चालकों ने हड़ताल की घोषणा कर दी। आटो चालकों का कहना है कि

पिछले एक सप्ताह से पुलिस ने बस अड्डा व मेन रोड पर आटो खड़ा करने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही ऑटो में संगीत बजाने और रंगीन लाइट का इस्तेमाल करने पर भी पुलिस द्वारा मारपीट की जाती है। बस अड्डे पर आटो खड़ा कर सवारी बैठाने पर जुर्माना वसूला जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनका रोजगार छीन लिया है। अब उनके सामने रोजी रोटी संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं, आटों चालकों की हड़ताल से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि, इस दौरान ई—रिक्शा चलते रहे, जिस कारण हड़ताल का खास असर नहीं

जाम का कारण बन चुके अतिक्रमण के खिलाफ यातायात पुलिस ने बुधवार को भी अभियान जारी रखा। यातायात पुलिस ने जीटी रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान चौधरी मोड़ से लेकर ठाकुरद्वारा तक सड़क को दोनों तरफ से बिल्कुल खाली करा दिया गया। इसके बाद बुधवार को जीटी रोड पर वाहनों ने फर्ाटे भरे। पुलिस ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी है कि यदि दोबारा सड़क पर कब्जा किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी यातायात राजेश कुमार ने बताया कि सीओ यातायात पवन कुमार व यातायात

निरीक्षक रमेश तिवारी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि सुबह साढ़े 11 बजे से अतिक्रमण के खिलाफ शुरुआत की गई और अभियान डेढ़ बजे तक चलाया गया। उन्होंने बताया कि चौधरी मोड़ से लेकर हापुड़ मोड़ तक सड़कों के दोनों तरफ खड़े ठेली, पटरी समेत वाहनों



हुआ। आटो चालकों ने दोपहर के समय हड़ताल को समाप्त कर दिया। दोपहर बाद सड़कों पर दोबारा से आटो दौड़ने शुरू हो गए। आसिफ, दिलदार, शाहनवाज, तालिब, आसिफ, अलाउद्दीन, राजा, स्वालिन, शादाब असलम आदि आटो चालकों ने पुलिस पर उत्पीडन करने का आरोप लगाया है। इस बारे में थानाध्यक्ष हरिदयाल यादव ने बताया कि ऑटो चालकों की मनमानी के चलते हाईवे पर जाम की समस्या बनी रहती है। पुलिस ने आटो को हाईवे पर खड़े करने पर रोक लगाई है, जिससे हाईवे पर जाम न लगे।

विशेष सीबीआई जज पवन कुमार तिवारी की अदालत में एनआरएचएम घोटाले में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला सहित कई आरोपी कोर्ट में पेश हुईं। सभी मामलों में अदालत ने अलग—अलग तारीख लगाई। एक मामले में जौनपुर के पूर्व सीएमओ डा. एसएन उपाध्याय के खिलाफ अदालत ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया। जौनपुर के तत्कालीन सीएमओ परिवार कल्याण डा. सहृदय नारायण उपाध्याय उर्फ डा. एसएन उपाध्याय ने लखनऊ के सर्जिकल एंड फार्मास्युटिकल के संचालक राजकुमार के साथ 2010 व 11 में दवाइयोंएवं अन्य सामानोंकी खरीददारी में एनआरएचएम मद से की।

दिलशाद गार्डन टू नया बस अड्डा मेट्रो फेज—2 प्रोजेक्ट की फंडिंग का मामला बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री सुरेश पासी की बैठक में भी उठा। जीडीए अफसरों की टीम ने राज्यमंत्री को उनके द्वारा मांगी गई बिंदुवार सूचना तो उपलब्ध कराई ही। इसके साथ पूर्व में पूरी हो चुकी व वर्तमान में जारी विकास योजनाओं के बारे में भी बारीकी से जानकारी दी। मेट्रो की फंडक्षडग का मामला इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ द्वारा ली गई बैठक में प्रमुख सचिव आवास सदाकांत द्वारा प्रकाश में लाया गया था। आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री ने बुधवार को लखनऊ में जीडीए समेत यूपी के कई विकास प्राधिकरणों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी। बैठक के

लिए राज्यमंत्री द्वारा अवैध निर्माण, प्लानिंग, इंजीनियरिंग और प्रॉपर्टी सेक्शन से संबंधित प्वाइंट्स भेजकर बिंदुवार रिपोर्ट मांगी गई थी। जीडीए के प्रभारी उपाध्यक्ष व सचिव रवीन्द्र गोडबोले के नेतृत्व में अफसर बैठक में शामिल हुए और राज्यमंत्री द्वारा मांगी गई सूचनाओं को बिंदुवार विस्तार से अवगत कराया गया। इसके साथ ही जीडीए अफसरों ने मेट्रो फेज—2 प्रोजेक्ट के फंडिंग पैटर्न के अनुसार नगर निगम, आवास विकास परिषद व यूपीएसआईडी द्वारा अपने हिस्से का अंशदान न देने के मामले को भी राज्यमंत्री को अवगत कराया। राज्यमंत्री के साथ जीडीए अफसरों की बैठक बुधवार दोपहर 11.45 बजे से एक बजे तक करीब सवा घंटे चली। जीडीए के प्रभारी उपाध्यक्ष के अलावा बैठक में ओएसडी दयानंद प्रसाद आदि मौजूद थे।

विशेष सीबीआई जज पवन कुमार तिवारी की अदालत में एनआरएचएम घोटाले में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला सहित कई आरोपी कोर्ट में पेश हुईं। सभी मामलों में अदालत ने अलग—अलग तारीख लगाई। एक मामले में जौनपुर के पूर्व सीएमओ डा. एसएन उपाध्याय के खिलाफ अदालत ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया। जौनपुर के तत्कालीन सीएमओ परिवार कल्याण डा. सहृदय नारायण उपाध्याय उर्फ डा. एसएन उपाध्याय ने लखनऊ के सर्जिकल एंड फार्मास्युटिकल के संचालक राजकुमार के साथ 2010 व 11 में दवाइयोंएवं अन्य सामानोंकी खरीददारी में एनआरएचएम मद से की।

दिलशाद गार्डन टू नया बस अड्डा मेट्रो फेज—2 प्रोजेक्ट की फंडिंग का मामला बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री सुरेश पासी की बैठक में भी उठा। जीडीए अफसरों की टीम ने राज्यमंत्री को उनके द्वारा मांगी गई बिंदुवार सूचना तो उपलब्ध कराई ही। इसके साथ पूर्व में पूरी हो चुकी व वर्तमान में जारी विकास योजनाओं के बारे में भी बारीकी से जानकारी दी। मेट्रो की फंडक्षडग का मामला इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ द्वारा ली गई बैठक में प्रमुख सचिव आवास सदाकांत द्वारा प्रकाश में लाया गया था। आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री ने बुधवार को लखनऊ में जीडीए समेत यूपी के कई विकास प्राधिकरणों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी। बैठक के



जाकर सांसद कौशल किशोर से मिला। उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष मिथलेश कुमारी ने बताया कि बुधवार को दिल्ली में सांसद से मिलकर सारी स्थिति से अवगत कराया तो उन्होंने बाल विकास मंत्री से बात कर आंगनबाड़ियों की सुनवाई करने के लिए कहा है। उधर, सीडीओ के आदेश पर सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर अनुपस्थित कार्यकत्रियों की रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक, अफसरों को भेजी गई करीब 80 कार्यकत्रियों की रिपोर्ट में 20 मुरादनगर क्षेत्र में अनुपस्थित मिलीं, जबकि 60 नगर क्षेत्र में।

Ghaziabad Municipal Corporation polls to be announced soon

GHAZIABAD: Elections for Ghaziabad Municipal Corporation (GMC) are likely to be announced soon with the term of its present council of members set to expire on July 13. State election commissioner S K Jaiswal held a meeting in this regard with Ghaziabad district magistrate Nidhi Kesarwani and municipal commissioner Abdul Samad via video-conferencing on The last election to the municipal corporation was held in 2012. The highest number of councillors in the municipal corporation at present belong to the BJP. The mayor, who is elected directly, also belongs to BJP. During the course of Saturday’s meeting,



discussions were held on a plan to implement the state government order for delimitation of municipal wards in the city. According to the order, the delimitation exercise will be carried out in accordance with the 2011 census figures. The number of wards in the city will be increased to 100, up from 80 fixed in the last delimitation exercise carried out in 2005. The exercise in 2005 had been carried out in accordance with Census of India 2001 figures.

Parents meet minister Atul

GHAZIABAD: In an effort to find a solution to their long-standing dispute with private schools pertaining to fee hike, holding of classes in basements and transportation charges among others, members of All School Parents Association (ASPA), a Ghaziabad-based parents’ body, met minister of state Atul Garg on Sunday. The parents requested the minister to provide a permanent and viable solution to the issues by raising the issue with chief minister Yogi Aditya Nath.

Ghaziabad to get 20 new wards

GHAZIABAD: Ghaziabad Municipal Corporation (GMC) has set the ball rolling for the delimitation of 20 new wards in the district, mayor Ashu Verma told councillors on Friday. Verma said the deadline for submission of the blueprint of the delimitation project to the district administration was April 12, 2017. According to GMC officials, a new ward will be created at a population segment of every 16,500 people across the district, with a negotiable margin of 15-

Docs under lens for lapses

Ghaziabad: The district administration on Monday directed departmental proceedings against a doctor in MMG District Hospital on charges of prescribing medicines to be purchased from the retail market. The decision comes after an inspection of the hospital premises by a team of administration officials led by DM Nidhi Kesarwani and ADM (City). The administration has also ordered withholding of one-day salary of 11 doctors who were found absent during duty hours on Monday. “One of the patients complained against a dermatologist who would prescribe medicines on a blank paper to be purchased from outside the hospital.

2 girls score a perfect 10 in first semester engineering exams

LUCKNOW: Only two engineering students, both girls, out of 39,583 who took their first semester exams (all five subjects) in December, 2016 secured 100% marks, that is, 10 Sessional Grade Point Average (SGPA). The students -Shivi Agarwal and Richa Kumari Sharma -belong to computer science and engineering branch from AKG Engineering College, Ghaziabad and IEC College of Engineering and Technology, G a u t a m b u d d h n a g a r respectively. Aishwarya Agarwal from KIET Group of Institutions, Ghaziabad bagged third position with SGPA of 9.88. With 29 out of 100, KIET Group of Institutions,



Ghaziabad had maximum number of students who scored above 9 SGPA, followed by AKG Engineering College, Ghaziabad with 15 students making it to top 100. Ghaziabad’s ABES Engineering College was adjudged the third best institute with 15 students appearing in top 100 list. While 12.54% students at AKG scored over 9 SGPA, the percentage at ABES College was 10.16%, keeping the latter at third place.

8 arrested for snatching, loot in Ghaziabad

GHAZIABAD: Eight men were arrested on Friday for their involvement in several cases of snatching and loot in Noida and Ghaziabad, Two persons were arrested in Sector 39, Noida and a stolen Maruti Swift car was recovered from their possession. Two mobile phone snatchers were arrested in Sector 20 and two mobile phones were recovered. In Phase III two men involved in theft were arrested and two stolen mobile phones and a bike were retrieved from them.

Tree stump blocks Hindon bridge entrance

GHAZIABAD: It’s been around two months since GDA felled a tree that was blocking the entrance to the newly constructed Hindon Bridge. But the concrete base of the tree remains intact. The base has been congesting traffic movement, apart from posing the risk of accidents. The forest department gave a clearance for felling the tree two years after the bridge was thrown open. It’s a classic case of government departments passing the buck. During construction of the 170-metre-long bridge, the forest department did not accord clearance for chopping the tree

located on the right side of its entrance. So GDA built a concrete roundabout around the tree and went ahead with the construction work. In March 2015, GDA threw open the bridge to commuters with the tree and its concrete base blocking nearly half of the 7.5-metre-wide entrance. Clearance for chopping the tree was accorded to GDA in January 2017, nearly two years after the bridge was opened for traffic. GDA paid the forest department for planting 10 trees in lieu of the one to be felled in keeping with the terms and conditions of the clearance.

Stir against liquor store near hostel

GHAZIABAD: Nearly 80 protesters gathered near Santosh Medical College Girls’ Hostel in Vijayanagar’s Pratap Vihar area on Sunday and demanded immediate closure of a liquor shop in the area. The protesters, who included shopkeepers and residents, blamed the liquor store for triggering traffic jams and safety concerns. In a bid to calm down the protesters, police prohibited the entry to first floor of the store which has a sitting space for customers. Deep Yadav, president, Line Park Vyapar Mandal Sector 12, Pratap Vihar said added several drunken brawls have been reported in the area triggering safety concerns.

Leopard strays into Ghaziabad’s residential area, injures two

GHAZIABAD: A full grown male leopard was rescued from a house in Bhopura’s Krishna Vihar Kuti, in Sahibabad area in the wee hours of Friday but not before injuring two people. The leopard was first spotted in the residential area on Thursday night at around 9 pm creating panic among residents. In a bid to escape, the leopard somehow entered a house and was confined in a room when an alert resident locked it from outside. Soon forest department officials reached the spot and cordoned off the area by placing a net around all possible exits. “I had just returned from office and was

parking my bike when I suddenly noticed a leopard which attacked me” says Bittu, 32. “The leopard sunk his teeth in my arms and chest but I managed to shrug it off and it ran away” adds Bittu. He was rushed to GTB Hospital where first aid was administered, he was discharged later. The leopard then made its way into the house of one Satpal whose twenty-one-year-old daughter Preeti fled to the terrace when she saw the animal approaching. “I noticed it approaching and raced towards the terrace while shouting “tendua ghus aaya hai” says Preeti.

vkj Vhvkseacu jgk u; k fj dkMZ: e

xkft; kckn % आरटीओ कार्यालय में अब फाइल ढूँढ़ने के लिए समय नहीं लगेगा। इसके लिए नया रिकार्ड रूम बनाया जा रहा है जो कंप्यूटरीकृत होगा। एक क्लिक में फाइल से संबंधित लेखा—जोखा कर्मचारियों से सामने होगा। शासन द्वारा इसके लिए बजट स्वीकृत हो चुका है। सारथी भवन के ऊपर एक मंजिल का निर्माण किया जाना है। चार माह पूर्व इस संबंध में विभाग द्वारा प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया था। इसके बाद आचार संहिता लागू हो गई। इस वजह से प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव संपन्न होते ही प्रस्ताव को स्वीकृत मिल गई है। सारथी भवन के ऊपर बनने वाली मंजिल में रिकार्ड रूम को स्थानांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे विभागों को स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे सीधे आम लोगों का वास्ता नहीं है। वाहनों के

tw l s'kq gksk dke

इस दिषा में जून से काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए डिजाइन आदि तैयार कराया जाएगा और इसे लखनऊ मुख्यालय स्वीकृत के लिए भेजा जाएगा। डिजाइन स्वीकृत होने के बाद काम शुरू हो जाएगा।

रिकार्ड के साथ—साथ परमिट रिकार्ड रूम को भी स्थानांतरित किया जाएगा। सारथी भवन के ऊपर बनने वाला नया रिकार्ड रूम पूरी तरह से हाईटेक होगा। यह पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड बनाया जाएगा, जिससे फाइलों को ढूँढ़ने में समय नहीं लगेगा। कंप्यूटर में गाड़ी का नंबर डालते ही पता चल जाएगा कि फाइल किस रैंक में रखी है और इस तरह कर्मचारी तुरंत फाइल निकालकर ले आएगा। मौजूदा समय में संभागीय परिवहन कार्यालय में नौ लाख वाहनों के

रिकार्ड मौजूद हैं। इसके लिए चार कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। चूंकि मौजूदा रिकार्ड रूम पुराना है इसलिए सीलन आती रहती है, जिससे फाइलों को नुकसान भी पहुंचता है। नए रिकार्ड रूम में सीलन आदि से राहत मिलेगी। नई मंजिल का निर्माण इस तरह किया जाएगा, जिससे अंदर धूप और रोशनी लगातार आए। रिकार्ड रूम को कैमरों की जद में रखा जाएगा, जिससे रूम लगातार अधिकारियों की निगरानी में रहेगा। दोनों आरटीओ और एआरटीओ प्रवासन अपने—अपने कमरों से नजर रखेंगे। वहीं एआरटीओ प्रवासन विष्वजीत प्रताप सिंह का कहना है कि रिकार्ड रूम के लिए बजट स्वीकृत हो गया है। इस संबंध में मुख्यालय से सूचना आ चुकी है, अगले सप्ताह तक स्वीकृत पत्र आ जाएगा। इसके बाद डिजाइन आदि का काम शुरू हो जाएगा।

15 साल में जीडीए को दिखे मात्र 18337 अवैध निर्माण

xkft; kckn % गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को बीते 15 साल में शहर में सिर्फ 18337 अवैध निर्माण ही दिखाई दिए। इसमें 7961 अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग और 3854 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। 6522 अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जीडीए के स्तर पर पेंडिंग हैं। जीडीए क्षेत्र में अवैध निर्माण का यह आंकड़ा एक अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2017 तक का है। शहर में अवैध निर्माण की स्थिति को देखते हुए जीडीए का यह आंकड़ा असलियत से कोसों दूर नजर आता है। अवैध निर्माण कर शहर की सूरत बिगाड़ने का कारनामा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) अफसरों की शह पर होता है। यह सच किसी से छिपा नहीं है। पूरे शहर में अफसरों की मिलीभगत से प्लानिंग का बेड़ा गरक कर दिया गया। नक्शे से ज्यादा विपरीत निर्माण कराकर

शहर की दशा तो बिगाड़ी ही गई। साथ ही आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से दुकानें बना कर प्लानिंग का सत्यानाश करने का काम भी जीडीए अफसरों की मिलीभगत पर हुआ। वर्तमान में आवासीय क्षेत्र में आलम ये है कि अवैध रूप से बनी दुकानों के बाहर ग्राहकों की गाड़ियां खड़ी हो जाती है और जीडीए द्वारा बसाई गई आवासीय कॉलोनी में लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। यहां खास बात यह है कि जीडीए की हर कॉलोनी में दूसरे—तीसरे घर में अवैध निर्माण होने के बावजूद प्राधिकरण को 15 सालों में सिर्फ 18337 अवैध निर्माण ही दिख सके। दरअसल, साठगांठ न हो पाने वाले मामलों में प्राधिकरण अफसरों द्वारा नोटिस व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। कई मामलों में फंसने के डर से अफसर साठगांठ होने के बावजूद भी नोटिस जरूर काटते हैं।

'kjkC Bds i j efgyk vkausfd; k çn' kũ

xkft; kckn % निवाड़ी रोड स्थित शराब ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर जगतपुरी व डिफेंस कॉलोनी की दर्जनों महिलाओं ने बुधवार को शराब ठेके पर हंगामा किया। महिलाओं ने ठेके पर मौजूद कर्मचारियों को चेतावनी दी कि या तो वह स्वयं ठेके को बंद कर दें अन्यथा महिलाएं खुद अपने हाथ में कानून लेकर ठेके को बंद करा देंगी। हंगामा करने वाली महिलाओं को पुलिस ने समझाकर बामुश्किल शांत किया। बुधवार दोपहर को निवाड़ी रोड स्थित डिफेंस कॉलोनी एवं जगतपुरी की दर्जनों

f'kdk; rkædsfuLrkj.k dh j'fdæ ea tuin 13oai k; nku ij

xkft; kckn % फरियादियों की शिकायतों की सुनवाई पर हाल ही में हुई रैंकिंग में जनपद 17वें स्थान से 13वें पायदान पर पहुंच गया है। वहीं नगर निगम और पुलिस विभाग में शिकायतों के अंबार और निस्तारण में सुस्ती बदस्तूर जारी है। जनपद के लोगों की डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचने वाली शिकायतों पर शासन की विशेष नजर है। शिकायतों के निस्तारण के लिए अफसरों की हामी ही नहीं, बल्कि पीडित की संतुष्टि को तवज्जो देने के कड़े निर्देश हैं। शासन की सख्ती पर अफसरों ने सुनवाई पर गंभीरता बरतनी शुरू की।

जनपद में 22000 बच्चे कुपोषित

xkft; kckn % जिले में 22 हजार से ज्यादा बच्चे अभी भी कुपोषण का शिकार हैं। ऐसा तब है जबकि करीब 11 हजार बच्चों को सामान्य करने का दावा विभाग ने किया है। बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। डीएम ने लापरवाही बरतने पर अफसरों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में डीएम ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। डीएम ने कहा कि पात्र राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। आपूर्ति विभाग के अफसरों ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में 515 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 208 राशन की दुकानें हैं, जिन पर कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। डीएम ने सत्यापन कर अपात्र राशन कार्ड

jkT; i k'sk.k fe'ku dh l eh{k k ea [kgykl k] djhc i k's nks yk[k dk fd; k Fkk otu

निरस्त करने के निर्देश दिए। राज्य पोषण मिशन की समीक्षा में बताया कि 172673 बच्चों का वजन किया गया। गत माह तक 11457 बच्चे अतिकुपोषित, जबकि 20758 कुपोषित चिह्नित किए गए। इनमें 10936 बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाया गया है। विद्युत विभाग के अफसरों ने बताया कि 2769 खराब ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं। डीएम ने गर्मी में निर्बाध विद्युत व पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए। इस अवसर पर महिला कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, सिंचाई, विकलांग कल्याण, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, पशुधन, समग्र ग्राम विकास, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण की समीक्षा की गई।

महिलाएं अपने पास के शराब ठेके पर पहुंची। महिलाओं ने पहले ठेके पर तैनात कर्मचारियों से शराब ठेके के मालिक के बारे में पूछताछ की। इसके बाद महिलाओं ने हंगामा करते हुए कर्मचारियों को चेतावनी दी कि वह अपने मालिक को सूचना देकर जल्द ही शराब ठेके को बंद कर दें अन्यथा महिलाएं खुद कानून हाथ में लेकर शराब ठेके को बंद कराने को विवश होंगी। महिलाओं के हंगामे को देख कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई। हंगामा होने की सूचना पाकर पुलिस और आबकारी निरीक्षक अरविंद राय

मौके पर पहुंचे और महिलाओं को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। अधिकारियों से महिलाओं ने शिकायत की कि शराब ठेके पर हर समय आसामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और वह आते जाते महिलाओं व लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इस बारे में आबकारी निरीक्षक का कहना है कि ठेका नियमों के तहत ही चल रहा है। यदि महिलाओं को इस पर आपत्ति है तो वह इस बारे में जिलाधिकारी से शिकायत कर सकती हैं। इस मौके पर सविता आदि समेत कई महिलाएं मौजूद रहीं।

xte i pk; rkæa tkjh jgæh VMj i fØ; k

xkft; kckn % जनपद की ग्राम पंचायतों में टेंडर प्रक्रिया और भुगतान जारी रहेंगे। शासन ने भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर दोबारा आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट करते हुए संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्तियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आचार संहिता हटने और नई सरकार गठन के बाद विकास कार्यों पर लगा ब्रेक भी हट गया। ग्राम पंचायतों सहित जिले भर में विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। करीब एक सप्ताह पहले शासन ने आदेश जारी कर 24 मार्च को ग्राम पंचायतों में होने वाले टेंडर और भुगतान के साथ ही संविदा और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने

का फरमान सुनाया था। साथ ही 11 मार्च के बाद हुई नियुक्तियों का ब्योरा भी तलब किया था। हालांकि 31 मार्च को शासन ने टेंडर और भुगतान पर लगी रोक हटाते हुए नियुक्तियों पर रोक जारी रखने रखने का आदेश दिया था। शासन के आदेश के बाद सूबे के कई जिलों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रमुख सचिव चंचल कुमार तिवारी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए पुनरु आदेश जारी किए हैं। उन्होंने पुराने आदेशों का हवाला देते हुए ग्राम पंचायतों में टेंडर और भुगतान जारी रखने को कहा है, जबकि संविदा और आउटसोर्सिंग से नियुक्तियों पर रोक के निर्देश दिए हैं।

BUREAU OFFICE
PRATEEK BHARGAVA
Bureau Chief
5, Ashok Vihar, 3rd Floor,
GMS Road, Nr. Ballupur
Chowk, Dehradun.
Mobile: +91 8130640011
Email: prateekb@tbcgzb.com
www.tbcgzb.com
Contact for Press Release
and Advertisements

BUREAU OFFICE
VIKRAM KUMAR
Bureau Chief
12/516, Friends Co-operative
Society Vasundhra,
Ghaziabad (UP)
Mobile: +91 8130640077
Email: vikram@tbcgzb.com
www.tbcgzb.com
Contact for Press Release
and Advertisements